झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका स. 4362/2018

------

1. देवेंद्र कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 73 वर्ष, पिता - स्वर्गीय बी. एल. अग्रवाल, निवासी लाल बंगला, धैया, डाक घर नागनगर, थाना. धनबाद, जिलाः- धनबाद

2. आदर्श कुमार अग्रवाल, आयु लगभग 43 वर्ष, पिता- देवेंद्र कुमार अग्रवाल, निवासी लाल बंगला, धैया, डाक घर. नागनगर, थाना. धनबाद, जिलाः- धनबाद ... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. जितेंद्र कुमार अग्रवाल, पिता- स्वर्गीय बी. एल. अग्रवाल, आयु लगभग 64 वर्ष, 1, चंचनी कॉलोनी, धैया, डाक घर नागनगर, थाना- धनबाद, जिला- धनबाद. ... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री आर. एस. मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्रीमती जे. मजूमदार, अधिवक्ता
श्री निशांत के. रॉय, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री प्रबीर के. चटर्जी, विशेष पी.पी.

उत्तरदाता नंबर 2 के लिए : श्री अमन दयाल सिंह, अधिवक्ता
श्री मोहित प्रकाश, अधिवक्ता
श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा सीपी केस नंबर 2621/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिससे और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी के तहत, धनबाद ने *प्रथम दृष्टया* अपराध आपराधिक विविध याचिका स.4362/2018 के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 420, 385, 504 के तहत दंडनीय पाया है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, ढांबा की अदालत में लंबित है

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 शिकायतकर्ता का भाई है और याचिकाकर्ता नंबर 2 याचिकाकर्ता नंबर 1 का बेटा है।याचिकाकर्ता संख्या 1 और शिकायतकर्ता के संयुक्त परिवार में कोई विभाजन नहीं हुआ है।याचिकाकर्ता संख्या 1 ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के कर्ता के रूप में, संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में एक बिक्री-विलेख निष्पादित किया है जिसमें दावा किया गया है कि बेची गई संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति है और याचिकाकर्ता संख्या 1 यह भी दावा कर रहा है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में विभाजन हुआ है।यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों में से एक के संबंध में शिकायतकर्ता के पक्ष में एक बिक्री-विलेख निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि विचाराधीन संपत्ति किसी भी बोझ से मुक्त है।बिक्री-विलेख के निष्पादन के बाद, शिकायतकर्ता ने उक्त संपत्ति को अपने नाम से परिवर्तित कर लिया है और उसी का आनंद ले रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 1 ने एक स्वामित्व मुकदमा दायर करने के मुकदमा एक शिव कुमार खेमका की स्थापना की है, जिसके द्वारा शिव कुमार खेमका याचिकाकर्ता संख्या 1 से संबंधित संपत्ति के खरीदार होने का दावा करते हैं, इससे पहले कि शिकायतकर्ता द्वारा इसे खरीदा गया था।शिकायत के

आधार पर, शिकायतकर्ता की गंभीर पुष्टि पर बयान और जांच गवाहों के बयान के आधार पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की खंड 420,385,504 के साथ 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए *प्रथमदृष्टया* मामला पाया है और सम्मन देना जारी करने का निर्देश दिया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच कई स्वत्वाधिकार वाद और विभाजन वाद के रूप में दीवानी वाद लंबित हैं और इस स्वीकृत तथ्यों से पता चलता है कि यह आपराधिक मामला केवल याचिकाकर्ता पर अवैध ब्लैकमेलिंग और शिकायतकर्ता की मांगों के आगे झुकने का दबाव बनाने के लिए दायर किया गया है।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन भूमि मेसर्स फाउंड्री ईंधन उत्पाद लिमिटेड द्वारा वर्ष 1986 में एक पंजीकृत बिक्री-विलेख द्वारा खरीदी गई थी।प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता संख्या 1 और शिकायतकर्ता दोनों उसी के शेयरधारक थे न कि निदेशक।याचिकाकर्ता संख्या 1 बाद में मेसर्स फाउंड्री ईंधन उत्पाद लिमिटेड का निदेशक बना और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत होने के बाद, कार्यालय परिसर से संबंधित भूमि को बेचकर शिकायतकर्ता को हस्तांतरित कर दिया और शिकायतकर्ता इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि सह-अभियुक्त शिव कुमार खेमका द्वारा स्वामित्व का दावा किया गया है, लेकिन शिव कुमार खेमका के दावे का समाधान किए बिना, शिकायतकर्ता के आग्रह पर, याचिकाकर्ता ने उक्त परिसर को स्थानांतरित कर दिया।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित बिक्री-विलेख दिनांक 29.04.1986 को कभी भी किसी सक्षम अदालत में चुनौती नहीं दी गई है या उससे पूछताछ नहीं की गई है और याचिकाकर्ता संख्या 1 के पास दिनांकित 29.04.1986 बिक्री विलेख द्वारा शिकायतकर्ता को हस्तांतरित करने का अधिकार था।हालाँकि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने कंपनी के निदेशक की क्षमता में बिक्री-विलेख को निष्पादित किया, लेकिन कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया है।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में स्वामित्व का निर्णय सक्षम दीवानी अदालत द्वारा किया जाना है और केवल इसलिए कि शिव कुमार खेमका ने दावा किया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पास कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प के संदर्भ में शिकायतकर्ता के पक्ष में बिक्री-विलेख के निष्पादन की तारीख पर कोई अधिकार नहीं था।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इस मामले के अलावा, शिकायतकर्ता ने 2014 का शिकायत मामला संख्या 2703 भी दर्ज किया है।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि संयुक्त परिवार की विभाजित संपत्ति है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने 40 साल पुराने आंशिक विभाजन के दस्तावेज को परिवार व्यवस्था का ज्ञापन दिनांक 30.12.1981 द्वारा दबा दिया है; हालाँकि शिकायतकर्ता द्वारा इस अदालत मे आपराधिक रिट याचिका संख्या 138 और आपराधिक रिट याचिका संख्या 239/2015 में दायर अपने जवाबी-हलफनामे में इस पर विवाद नहीं किया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी. एल. अग्रवाल (एच. यू. एफ.) का पूर्ण विभाजन और अलगाव शिकायतकर्ता और उसके चार भाइयों के बीच आई. डी. 1 पर हुआ था, जिसे शिकायतकर्ता और उसकी मां सहित सभी भाइयों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आई. डी. 2 दिनांकित ज्ञापन में विधिवत दर्ज किया गया था और प्रत्येक सदस्य के हिस्से में आने वाली संपत्ति की सूची को ज्ञापन में अनुसूची के रूप में संलग्न किया गया था।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी. एल. अग्रवाल (एच. यू. एफ.) के विभाजन का तथ्य भी आयकर अधिकारियों द्वारा आदेश किया गया था जब कानून के तहत इसके मूल्यांकन के लिए मामले रखे गए थे और 14.01.1983 के आदेश के अनुसार, विभाजन के दावे को आदेश किया गया था और आदेश करने के बाद अनुमति दी गई थी कि शिकायतकर्ता सहित प्रत्येक सदस्य ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि विभाजन हुआ है और उसे अपना हिस्सा मिल गया है।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि उप-न्यायाधीश VII, धनबाद की अदालत के 2003 के टाइटल मुकदमा संख्या.40 में दायर लिखित बयान में शिकायतकर्ता ने अपने लिखित बयान के पैरा-15 में परिवार के विभाजन के बारे में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।शिकायतकर्ता ने मेसर्स बी. एल. ए. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड साथ अपना सारा हिस्सा 27.09.1991 पर बेच दिया और मेसर्स अनूप माल्लीबल्स लिमिटेड में अपने, अपनी पत्नी और नाबालिग बेटों के शेयरों को भी मेसर्स बी. एल. अग्रवाल और बेटे प्राइवेट लिमिटेड को मूल्यवान प्रतिफल के लिए बेच दिया, जिसके साथ शिकायतकर्ता का उस समय कोई संबंध नहीं था।शिकायतकर्ता ने यशोबन सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड से संबंधित अपने विवाद के संबंध में 2011 का शीर्षक मुकदमा संख्या.78 भी दायर किया, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 8 के तहत 5 द्वारा खारिज कर दिया गया था। 28.07.2017 पर न्यायालय का अध्ययन किया।इसके

बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने भूमि के संबंध में सी.आर.पी.सी.की धारा 144 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी थी, लेकिन एस.डी.ओ ने 04.04.2011 के आदेश के माध्यम से कार्यवाही को छोड़ दिया।शिकायतकर्ता ने 2013 का शीर्षक (विभाजन) मुकदमा संख्या.151 भी दायर किया है और याचिकाकर्ता उस मुकदमे में पेश हुआ और अदालत द्वारा कभी भी कोई स्थगन स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

5. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **थर्मैक्स लिमिटेड और अन्य बनाम के. एम. जॉनी और अन्य** (2011) 13 एस. सी. सी.412 के मामले में पैरा-37 में रिपोर्ट किए गए फैसले पर निर्भर करते हैं, जिसमें से निम्नानुसार हैः-

> *"37. यह तय कानून है कि धारा 420 के तहत अपराध के लिए आवश्यक खंड, जिसे हम पहले ही निकाल चुके हैं, यह है कि किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने का बेईमान इरादा होना चाहिए।हम पहले ही शिकायत में प्रासंगिक आरोपों का हवाला दे चुके हैं और उसी के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस तरह के किसी भी बेईमान इरादे को नहीं देखा जा सकता है या यहां तक कि अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि पूरा विवाद पक्षों के बीच संविदात्मक दायित्वों से संबंधित है।चूँकि खंड 420 के तत्व ही आकर्षित नहीं हैं, इसलिए शुरू किया गया अभियोजन पूरी तरह से असमर्थनीय है।भले ही हम स्वीकार करते हैं कि शिकायत में आरोप एक विवाद बनाते हैं, फिर भी यह माना जाना चाहिए कि यह केवल अनुबंध का भंग है और यह धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को लेनदेन की शुरुआत से ही नहीं दिखाया जाता है।चूंकि यह दिखाने के लिए कई दस्तावेज हैं कि अपीलकर्ता कंपनी ने समझौते के संदर्भ में और प्रामाणिक तरीके से काम किया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता कंपनी का कार्य अनुबंध का भंग है।" (जोर दिया गया)*

और प्रस्तुत करता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध का गठन आदेश के लिए किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने का बेईमान इरादा होना चाहिए और केवल अनुबंध का भंग आपराधिक कार्यवाही को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि धोखाधड़ी या बेईमान इरादा लेन-देन की शुरुआत से ही सही नहीं दिखाया जाता है।

6. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य ने **(2005)** के **10 एस. सी. सी. 228** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करते हैं पैराग्राफ-8 में रिपोर्ट किया

जो नीचे लिखा हैः-

> *“8. शिकायत का सार देखा जाना चाहिए।शिकायत में केवल "धोखाधड़ी" शब्द का उपयोग करने से कोई लाभ नहीं होता है।मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत में "धोखा दें" और "धोखा दें" और पुलिस के समक्ष दायर शिकायत में "धोखा दें" शब्दों के उल्लेख के अलावा, समझौता ज्ञापन में प्रवेश करते समय आरोपी के धोखे, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के इरादे के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को भुगतान करने के लिए धोखा देने का था।शिकायतकर्ता के अनुसार, कुल राशि 3,05,39,086 में से 860 रुपये का भुगतान किया गया था और शेष राशि 33,23,774 छोड़ दी गई थी।हमें शिकायत में उल्लिखित राशि के अंतर के सवाल में जाने की आवश्यकता नहीं है जो नोटिस में उल्लिखित राशि से बहुत अधिक है और आरोपी के बचाव और नोटिस के जवाब में लिया गया रुख भी क्योंकि शिकायतकर्ता का अपना मामला यह है कि तीन करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था और शेष राशि के लिए, आरोपी ऊपर बताए गए कारणों को बता रहा था।इन पहलुओं में नहीं जाने का अतिरिक्त कारण यह है कि विचाराधीन राशियों के मुकदमा पक्षों के बीच एक दीवानी मुकदमा लंबित है।”*

और प्रस्तुत करता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध से जुड़ी शिकायत में, समझौता ज्ञापन में प्रवेश करते समय आरोपी के छल, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के इरादे के बारे में विशिष्ट अभिकथन किया जाना है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को भुगतान करने के लिए धोखा देने का था।इसलिए, इसने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की खंड 420 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनाया गया है।

7. इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि दीवानी मुकदमे के मामलों में, शिकायत में किए गए ऐसे किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया गया है और यह शिकायतकर्ता के मामले के झूठ को दिखाने के मुकदमा एक प्रासंगिक कारक है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए ऑल कार्गो मूवर्स (इंडिया) प्राइवेट के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं।

लिमिटेड और अन्य बनाम धनेश बदरमल जैन और एक अन्य ने (2007) 14 में रिपोर्ट किया

एस. सी. सी. 776 का अनुच्छेद-16 निम्नानुसार हैः-

"16. [एड.:पैरा 16 को आधिकारिक शुद्धिपत्र सं. एफ.3/एड.बी.जे./86/2008 दिनांकित 18-10-2008।]हमारी राय है कि शिकायत याचिका में लगाए गए आरोप, भले ही अंकित मूल्य दिए गए हों और पूरी तरह से सही माने गए हों, अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।उक्त प्रयोजन के मुकदमा, यह न्यायालय न केवल स्वीकृत तथ्यों पर विचार कर सकता है, बल्कि वाद में प्रतिवादी 1-वादी के अभिवचनों पर भी विचार करने की अनुमति है।नोटिस में अपीलार्थियों के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था।दावा किया गया कि वाहकों और उनके एजेंट की ओर से लापरवाही और/या अनुबंध का भंग किया गया था।संविदात्मक सरलीकरण का भंग अपराध नहीं है।उक्त उद्देश्य के लिए, शिकायत याचिका में आरोपों को उसके लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करना चाहिए।जहां एक दीवानी मुकदमा लंबित है और दीवानी मुकदमा दायर करने के एक साल बाद शिकायत याचिका दायर की गई है, हम यह पता

लगाने के उद्देश्य से कि क्या उक्त आरोप प्रथमदृष्टया सही हैं, पक्षों द्वारा आदान-प्रदान किए गए पत्राचार और अन्य स्वीकृत दस्तावेजों को ध्यान में रख सकते हैं।यह कहना एक बात है कि इस समय न्यायालय अभियुक्त के बचाव पर विचार नहीं करेगा, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि इस न्यायालय निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए, स्वीकार किए गए दस्तावेजों को देखना भी अस्वीकार्य है।आपराधिक कार्यवाही को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है।उच्च न्यायाधीशालयों को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए।"

और प्रस्तुत करता है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि यह पता लगाने के उद्देश्य से कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही हैं या नहीं, न्यायालय न केवल स्वीकार किए गए तथ्यों पर विचार कर सकता है, बल्कि आपराधिक मामले से पहले स्थापित पक्षों के बीच दीवानी मुकदमों में आरोपी व्यक्तियों के अभिवचनों पर भी गौर करने की अनुमति है।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकृति के मामलों की निंदा की है जहां विवाद विशुद्ध रूप से और मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है; इसे आपराधिक अपराध का आवरण नहीं दिया जाना चाहिए।

8. इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 385 या 504 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनाया गया है।अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा 2016 के सी. पी. मामले में पारित आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

9. राज्य की ओर से उपस्थित हुए और विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध का जोरदार विरोध किया कि वे धनबाद के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी द्वारा 2016 के सी. पी. मामले में पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दें, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है और यह सुझाव देने के लिए अभिलेख में पर्याप्त सामग्री है कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर और बेईमानी से शिकायतकर्ता को रुपये के साथ भाग

लेने के लिए प्रेरित किया है। विक्रय विलेख को निष्पादित करने का उद्देश्य।इसलिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है।विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 09.01.2012 एमओयू के खंड संख्या.06 सहित नियमों और शर्तों पर कार्य नहीं किया है।इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420,385,504 के साथ 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए *प्रथमदृष्टया* मामला सही पाया है।अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

10. बार द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख द्वारा उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता संख्या 1 दोनों का स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा शिकायतकर्ता को बेची गई संपत्ति के संबंध द्वारा कुछ विवाद था क्योंकि दावा शिव कुमार खेमका ने यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ऐसा विवाद है, शिकायतकर्ता इस बात पर जोर दे रहा था कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और शिकायतकर्ता के बीच कथित बिक्री लेनदेन में शिव कुमार खेमका को एक पक्ष बनाया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 1 ने बिक्री-विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया, जिससे शिव कुमार खेमका उक्त बिक्री लेनदेन में एक पक्ष बन गए क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थे कि शिव कुमार खेमका भी बिक्री-विलेख के निष्पादन में भाग लेते हैं, लेकिन शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 1 पर दबाव डाला और बिक्री-विलेख को निष्पादित कराया।शिकायत में कहीं भी, शिकायतकर्ता की गंभीर पुष्टि पर बयान में या जांच गवाहों के बयान में, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पास उस संपत्ति के संबंध में अधिकार नहीं था जिसे उसने शिकायतकर्ता को बेच दिया था।शिकायतकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि बिक्री-विलेख के परिणामस्वरूप, भूमि को उसके नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन बाद में शिव कुमार खेमका ने बेची गई संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया है और शिकायतकर्ता इस धारणा में है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने शिव कुमार खेमका को एक मुकदमा बनाने और शिकायतकर्ता को परेशान करने के मुकदमा स्थापित किया है।जैसा कि इस निर्णय के

पूर्वगामी पैराग्राफ में ऊपर उल्लेख किया गया है, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि भारतीय दंड संहिता की खंड 420 के तहत दंडनीय अपराध का गठन आदेश के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी का इरादा शुरुआत से ही धोखा देने का था और अगर धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है तो यह धोखाधड़ी का अपराध नहीं होगा जैसा कि उमा शंकर के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दोहराया गया है।

उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और एक अन्य की रिपोर्ट के पैरा-6 में **(2005) 10 एस. सी. सी. 336** जिनमें से कुछ इस प्रकार हैः-

"6. अब हमारे द्वारा जांच किए जाने वाला सवाल यह है कि क्या शिकायत की याचिका में प्रकट किए गए तथ्य किसी भी आपराधिक अपराध को भा.दं.सं. सी. की धारा 420/120-बी के तहत बहुत कम अपराध माना जाता है। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत याचिका में एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि जब उन्हें 4,20,000 की राशि का बीमा दावा प्राप्त होगा, तो वे शिकायतकर्ता को उसमें से 2,60,000 की राशि का भुगतान करेंगे, लेकिन इसका भुगतान कभी नहीं किया गया है।इसके अलावा शिकायत की याचिका में कोई अन्य आरोप नहीं है।शिकायतकर्ता की ओर से यह बताया गया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता को सहमत होने के लिए राजी किया ताकि आरोपी व्यक्ति रुपये 4,20,000 के दावे के संबंध में उपभोक्ता मंच को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा <u>सकें।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुबंध का प्रत्येक भंग धोखाधडी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का भंग धोखाधडी के बराबर होगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधडी की गई थी।यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखा नहीं हो सकता है</u>।वर्तमान मामले में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था जो आई. पी. सी. की खंड 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।"

(जोर दिया गया)

11. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, शिकायतकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने एक बिक्री-विलेख निष्पादित करने के बाद; निर्विवाद रूप से जिस पर उसका अधिकार, स्वामित्व और ब्याज था और जिसके परिणामस्वरूप बिक्री-विलेख निष्पादित होने पर, भूमि को खरीदार के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है जो शिकायतकर्ता है; मुकदमेबाजी करने के मुकदमा शिव कुमार खेमका की स्थापना की गई है और शिव कुमार खेमका द्वारा स्थापित स्वामित्व मुकदमा अभी भी विचाराधीन है।किसी भी अदालत ने विचाराधीन संपत्ति पर शिव कुमार खेमका के अधिकार, स्वामित्व और हित की घोषणा नहीं की है।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने शिकायतकर्ता को किसी भी संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया।ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से सच माना जाता है, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है।

12. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 385 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 385 के तहत अपराध के तत्व हैंः

(i) अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के डर में डाल दिया या डालने का प्रयास किया

(ii) व्यक्ति को इस तरह के डर में डालना जानबूझकर होना चाहिए।

(iii) अभियुक्त को इस प्रकार भय में पड़े व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या किसी हस्ताक्षरित या मुहरबंद चीज़ को देने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है और ऐसा प्रलोभन बेईमानी से किया जाना चाहिए जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।

आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले और एक अन्य का मामला ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 2045 में और अब्दुलवाहब अब्दुलमाजिद शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य के मामले में भी (2007) 4 एस. सी. सी. 257 में रिपोर्ट किया गया।

13. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है कि जबरन वसूली का अपराध मालिक की इच्छा पर अधिक बल देकर किया जाता है।अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतकर्ता या किसी और को चोट लगने के डर में डालने या डालने का प्रयास करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।पक्षों के बीच बातचीत में दिए गए प्रस्ताव को कि मेरा तरीका या कोई तरीका नहीं; किसी भी व्यक्ति को चोट के डर में डालने या डालने का प्रयास नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप भले ही पूरी तरह से सही माने जाएं, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 385 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

14. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि माननीय 12 द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य & एक अन्य के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की **रिपोर्ट (2019) 14 एस. सी. सी. 207 पैरा-24 में दी गई है जो निम्नानुसार हैः-**

> *"24. अब, हम अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों पर वापस आते हैं।आरोप यह है कि अपीलकर्ता दो या तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ, जिनमें से एक के पास रिवॉल्वर थी, शिकायतकर्ता के घर आया और उसे गंदी भाषा में गाली दी और उस पर हमला करने का प्रयास किया और जब कुछ पड़ोसी वहां पहुंचे तो अपीलकर्ता और उसके साथ आए अन्य व्यक्ति मौके से भाग गए।उपरोक्त आरोप अपने अंकित मूल्य को लेते हुए धारा 504 और 506 के तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में गिना गया है।<u>जानबूझकर अपमान</u>*

<u>इस हद तक होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाया जाए।केवल यह आरोप कि अपीलकर्ता आया और शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया,</u> फियोना श्रीखंडे [फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 44:(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 715](जोर दिया गया)

कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध का गठन आदेश के लिए, जानबूझकर अपमान इस तरह का होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति को तोड़ने या कोई अन्य अपराध आदेश के लिए उकसाता हो।

15. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जानबूझकर शिकायतकर्ता या किसी और का अपमान करने का कोई आरोप नहीं है और न ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतकर्ता को कोई उकसाने का कोई आरोप है, यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे से उसे या किसी और को सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना है और इन आवश्यक तत्वों के बारे में कोई सामग्री की अनुपस्थिति में पर, इस अदालत का विचार है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध नहीं किया जाता है, भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप, गंभीर पुष्टि पर शिकायतकर्ता का बयान और जांच गवाहों के बयान को लिया जाता है। अपनी संपूर्णता में सच्चे रहें।

16. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,385,504 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनाया गया है, इसलिए उनके खिलाफ इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें 2016 के सी. पी. मामले में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

17. तदनुसार, धनबाद के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी द्वारा दिनांकित 31.03.2017 के सी. पी. संख्या.2621/2016 के मामले में पारित आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, धनबाद की

अदालत में लंबित है, याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध के अनुसार, रद्द कर दी जाती है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग कर दी जाती है।

18. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

19. तात्कालिक आपराधिक विविध याचिका के निपटारे के मद्देनजर, अंतरिम राहत अनुदानकर्ता पहले दिनांक 06.01.2020 के आदेश के माध्यम से खाली हो गया है।

20. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटारे को देखते हुए, लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, को निष्फल होने के रूप में निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
12 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष-सरोज

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।